विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

भारत सरकार ने निम्नलिखित मामलों में मलेशियाई अधिकारियों को सहयोग देने की पेशकश की है :—

(i) हवाई पत्तन—भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण द्वारा ।

(ii) रेलवे—रेल-भारत तकनीकी व आर्थिक सेवा लिमिटेड (रेल-इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड) ।

(ख) जी हां ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण और रेल-भारत तकनीकी व आर्थिक सेवा लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने समकक्ष मलेशियाई अधिकारियों से वार्ता की है तथा राजनयिक माध्यमों से भी बातचीत हुई है ।

(ग) यद्यपि रेल-भारत तकनीकी व आर्थिक सेवा लिमिटेड और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण द्वारा काम पाने के लिए बातचीत चल रही है, इन दोनों संगठनों को आशा है कि वे मलेशियाई अधिकारियों के साथ फलप्रद सहयोग कर सकेंगे । मलेशियाई रेल अधिकारियों को 'इरकोन' द्वारा की गई पेशकश पर विचार किया जा रहा है । दोनों देशों के परस्पर लाभार्थ सिबु हवाई पत्तन के निर्माण के लिए अपने मलेशियाई समकक्ष अधिकारियों की ओर से सहयोग संबंधी अद्यतन प्रस्ताव, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

उगांडा से निष्कासित भारतीय

1486 श्री तारिक अनवर :
श्री होरा लाल आर० परमार :
श्री केशव राव पारधी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उगांडा से निष्कासित गैर-निवासी भारतीयों के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का कालानुक्रमिक ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग). अमीन शासन के दौरान भारतीय मूल के उगांडाई राष्ट्रिकों को निष्कासित किए जाने के प्रश्न को उस देश की स्वतन्त्रता के बाद उगांडा सरकार के साथ उठाया गया था । उगांडा सरकार ने बताया है कि भारतीय मूल के ऐसे सभी उगांडाई राष्ट्रिकों की वापसी का स्वागत है और उन के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो अन्य उगांडाई राष्ट्रिकों के साथ किया जाएगा । लेकिन 19 मई, 1979 को तत्कालीन राष्ट्रपति यूसुफ लुले ने कहा था कि उन की सरकार उन परिसरों और व्यापारों का गैर-अफ्रीकीकरण नहीं करेगी और न कर सकती है जिन्हें उगांडियों द्वारा ले लिया गया है ।

जहां तक उगांडा से निष्कासित किए गए भारतीय राष्ट्रिकों का संबंध है उगांडा और भारत की सरकारों ने इन लोगों द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति तथा अन्य परिसम्पत्तियों के लिए 1975 में एक मुआवजा समझौता किया गया था । चूंकि 1972 में निष्कासित किए गए इन भारतीय राष्ट्रिकों

के लिए मुआवजे के बारे में समझौता हो गया है, अत: सरकार इन भारतीय राष्ट्रिकों की वापसी के लिए उगांडा सरकार से सम्पर्क करने का विचार नहीं कर रही है ।

National Highways in Kerala

1487. SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) how many National Highways are in bad condition in Kerala at present;

(b) the amount of annual central allocation for the maintenance of these Highways;

(c) whether any amount was allowed to lapse during the last year; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) There are two National Highways *viz.* National Highway No. 17 and No. 47 in Kerala, and these are being maintained to the best possible extent subject to the overall availability of funds. Even though there have been extensive damages to these National Highways due to heavy and unprecedented rainfall during the recent past, both these National Highways have been maintained in traffic-worthy condition, and there has been no report of traffic hold-up on account of these damages.

(b) to (d). The funds for the maintenance and repairs of National Highways in Kerala are placed at the disposal of the State Government, after considering their requirement *vis-a-vis* the requirements of other States and the overall availability of funds earmarked for the purpose. The allotment made to the State Government and the expenditure incurred during the last five years, is indicated below:—

Year	Maintenance & Repairs of National Highways in Kerala	
	Allotment	Expenditure
	(Rs. in lakhs)	
1975-76	56·15	60·76
1976-77	58·02	59·60
1977-78	64·70	73·71
1978-79	85·55	96·57
1979-80	103·50	116·86
1980-81	152·03 (so far)	90·20*

*upto 12/80

As will be observed from the above table, expenditure exceeded the allotment during all these years, and no portion of the funds allotted lapsed.

DTC Service between Kamala Nehru Nagar Colony, Ghaziabad and Central Secretariat

1488. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kamla Nehru Nagar Colony in Ghaziabad is mainly for Central Government employees working in Delhi and Ghaziabad but there is no DTC or any other bus service from the colony to the Central Secretariat, Delhi or to Delhi and Ghaziabad Railway Stations; and

(b) by when such bus services would begin to ply?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The inter-state operation is required by reciprocal agreement between the concerned States. The DTC has been granted 10 permits by the State Transport Authority, Delhi in pursuance of such an agreement